

# भारत का राजपत्र The Gazette of India

अस.धारण  
EXTRAORDINARY  
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 36]

नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 17, 1976 पीप 27, 1897

No. 36]

NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 17, 1976/PAUSA 27, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

## MINISTRY OF INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES

(Department of Industrial Development)

### ORDER

*New Delhi, the 17th January 1976*

**S.O. 45(E)/18FB/IDRA/76.**—Whereas by the Order of the Government of India, in the late Ministry of Industrial Development (Department of Industrial Development) No. S.O. 35(E)/18FB/IDRA/73, dated the 19th January, 1973 (hereinafter referred to as the said Order), the Central Government in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), declared that the operation of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force immediately before the date of issue of the said Order (other than those relating to secured liabilities to banks and financial institutions) to which the industrial undertaking known as Messrs. India Machinery Company Limited, Howrah, is a party or which may be applicable to the said industrial undertaking shall remain suspended for a period of one year from that date and that all the rights, privileges, obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date of issue shall remain suspended for the said period;

And, whereas, the duration of the said Order was extended upto the 18th January, 1976;

And, whereas, the Central Government is satisfied that the duration of the said Order should be extended for a further period of one year;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with sub-section (2), of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby extends the duration of the said Order for a further period upto the 18th January, 1977.

[F. No. 25(26)/72-CUC]

D. K. SAXENA, Jt. Secy.

## उद्योग और नागरिक पुति मंत्रालय

## (औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 17 जनवरी, 1976

का० आ० 45 (अ)/18 एफ बी/आई डी आर ए/76.—भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का० आ० 35(अ)/18 च ख/उ० वि० वि० अ०/73, तारीख 19 जनवरी, 1973 द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) केन्द्रीय सरकार ने उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 च ख की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा की थी कि राजपत्र में उक्त आदेश के प्रकाशन के अथवा पूर्व प्रवृत्त ऐसी सभी या किसी संविदा, भूमि के हस्तान्तरण पत्र, करार, परिनिर्धारण, पंचाट, स्थायी आदेश या अन्य लिखत (उनसे भिन्न जो बैंकों या वित्तीय संस्थाओं के प्रतिभूति दायित्वों से सम्बन्धित हैं), जिनका मेसर्स इन्डिया मशीनरी कम्पनी लिमिटेड, हावड़ा नामक औद्योगिक उपक्रम एक पक्षकार है, या जो उक्त औद्योगिक उपक्रम को लागू हो, का प्रवर्तन एक वर्ष की अवधि तक निलम्बित रहेगा और उक्त तारीख के पूर्व उमके अधीन प्रोद्भूत या उद्भूत सभी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यताएँ और दायित्व उक्त अवधि तक निलम्बित रहेंगे ;

और उक्त आदेश की अवधि 18 जनवरी, 1976 तक बढ़ा दी गई थी ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त आदेश की अवधि एक वर्ष के लिए और बढ़ा दी जानी चाहिए ;

अतः अब उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 च ख की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त आदेश की अवधि 18 जनवरी, 1977 तक बढ़ाती है ।

[सं० फा० 25(26)/72-सी० यू० सी०]

डी० के० सक्सेना, सयुक्त सचिव ।